

कोशिश बहुत की है समझदार बनने की लेकिन खुशियां तो बेवकूफियां करने से ही मिलती है।  
- अज्ञात

## सोना ऐतिहासिक ऊंचाई पर

बीते बृहस्पतिवार को अपने यहां यह 57,700 रुपया प्रति दस ग्राम के भाव पर बिका। पस्ती के माहौल में सोने की यह चकाचौंध दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देती है, हालांकि अपने देश में सोने का ग्राफ जब-तब ही थोड़ा नीचे आता है, फिर जल्द ही ऊपर का रुख कर लेता है।

नवीन वर्मा।

आजकल हम असामान्य और कई मामलों में अभूतपूर्व दौर से गुजर रहे हैं। यह बात दूसरी तमाम चीजों के साथ-साथ सोने के लगातार चढ़ते भावों से भी जाहिर हो रही है। दुनिया के स्तर पर सोने में जबर्दस्त तेजी दिखाई दे रही है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में यह बीते मंगलवार 2000 डॉलर प्रति ट्रांय आउंस से ज्यादा हो गया। ट्रांय आउंस सोना और अन्य कीमती धातुओं का वजन नापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है और यह 31.1034768 ग्राम के बराबर होता है।

यह लगातार तीसरा हफ्ता है जब सोना 1900 डॉलर के बैचमार्क से ऊपर रहा। 2011 के बाद से यह पहला मौका है जब इतनी लंबी अवधि तक सोना इस ऐतिहासिक ऊंचाई पर बना रहा। बहरहाल,

भारत में सोने की ऊंचाई पर नजर डालें तो यह ग्लोबल से भी ज्यादा है। बीते बृहस्पतिवार को अपने यहां यह 57,700 रुपया प्रति दस ग्राम के भाव पर बिका।

पस्ती के माहौल में सोने की यह चकाचौंध दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर देती है, हालांकि अपने देश में सोने का ग्राफ जब-तब ही थोड़ा नीचे आता है, फिर जल्द ही ऊपर का रुख कर लेता है।

नब्बे के दशक में आए भूमंडलीकरण के दौर के बाद से देखें तो 1992 में यह 4334 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। साल-दर-साल घटते-बढ़ते हुए 1996 में एक बार 5000 की सीमा पार करने के बाद भी 2002 में यह पांच हजार के अंदर ही था। खासकर 2004 के बाद लंबी

छलांगें लगाते हुए 2012 में इसने पहली बार 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की सीमा पार की। हालांकि दोबारा यह करतब दिखाने में उसे छह साल लगे।

2018 में 31,438 पर आने के बाद पिछले साल इसकी ऊंचाई 35,220 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज की गई। यहां से देखने पर अंदाजा मिलता है कि इसकी मौजूदा ऊंचाई कितनी अस्वाभाविक है।

बहरहाल, समस्या वैश्विक है और इसे भारत तक सिमटाकर देखने का कोई औचित्य नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी मजबूरियों ने सारे निवेशों को गैर-भरोसेमंद बना दिया है। अमेरिका के दस वर्षीय ट्रेजरी नोट पर मुनाफा इस हफ्ते 0.52 फीसदी दर्ज किया गया जो अब तक का सबसे निचला

स्तर है। भारत में हालात कुछ मामलों में वहां से ज्यादा बुरे हैं। अपना पैसा कहीं भी रखना निवेशकों को सेफ नहीं लग रहा।

कोई सोच सकता है कि कुछ लोग सोने की खरीद-बिक्री से धुआंधार पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन यह प्रवृत्ति सोने में निवेश करके मुनाफा कमाने की उतनी नहीं है, जितनी टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे को निर्जीव पूंजी में बदल कर किसी गुप्त ठिकाने पर सुरक्षित रखने की। विशेषज्ञ उम्मीद जता रहे हैं कि यह रुझान ज्यादा नहीं चलेगा और दो-तीन महीने में हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अपने देश में धन को सोने की शकल में देखने की बीमारी इतनी पुरानी है कि यह कोरोना से जुड़े संकटों का एक और पहलू भी साबित हो सकती है।



## आशा रहित बना

अशोक बोहरा।

जैसे ही कोई आपको आशा की झलक देगा, आप कल्पनाएँ करने लगेंगे। आशा, झूठ का पुलिंदा बनाने का तरीका है। अगर आप आनंदमय रूप से आशा रहित होंगे, तो बात बन जाएगी। आप ऐसी जगह पहुँच पाएँ, जहाँ आप को किसी आशा की जरूरत न हो। फिर जो भी हो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर ही कुछ पा लिया है।

वास्तविकता के साथ जीना सीखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप को कुछ और नहीं करना है। अगर आप अपने मन में चीजों को तोड़ना, मरोड़ना, बिगाड़ना बंद कर दें और हरेक चीज को वैसी ही देखें जैसी वह है, तो मुक्ति आपसे बस एक कदम ही दूर है। आप को कुछ भी नहीं करना है, समय ही सब कर लेगा। समय आप को किसी और तरह से परिपक्व कर देगा।

धर्म-दर्शन



## संपादकीय

### व्यापक नेटवर्क चाहिए

शिक्षा और आर्थिक विकास की सीमित पहुंच के चलते समाज के बड़े हिस्से में बच्चों को कमाई का जरिया माना जाता रहा है, जबकि डेमोग्राफिक डिविडेंड की अवधारणा उन्हें शिक्षित-प्रशिक्षित कार्यशक्ति मानने पर आधारित है। ऐसे में पहली जरूरत बच्चों को लेकर लोगों की सोच बदलने, फिर उनके बीच गर्भनिरोधकों का व्यापक पैमाने पर मुफ्त वितरण करने और कोई जटिलता उत्पन्न होने पर उसका तात्कालिक समाधान निकालने के लिए व्यापक नेटवर्क विकसित करने की है। आज जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई भी योजना लागू करते समय व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सचार्च से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जनसंख्या नियंत्रण के अडि कांश कार्य कागजों पर ही चल रहे हैं। इस काम में लगी संस्थाओं में से ज्यादातर की दिलचस्पी प्रयासों को जमीन तक पहुंचाने से ज्यादा अपना फायदा सुनिश्चित करने में होती है। अपवादों को छोड़कर आज ये संस्थाएं लाभ कमाने के लिए ही कार्य कर रही हैं। सरकारी नीतियों का आलम यह है कि इस दौर में भी प्रलोभन देकर नसबंदी कराई जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट है कि प्रलोभन के आधार पर इस समस्या को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इससे भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा। लोगों में समय रहते यह समझदारी पैदा की जानी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि से देश का जो नुकसान होगा सो होगा, पर उससे पहले उनकी अपनी समस्याएं बढ़ जाएंगी। जब तक हम इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना एक दिवास्वप्न ही बना रहेगा।

हाल में चर्चा उठी कि शुरुआती हठ के बाद राहुल गांधी दोबारा पार्टी अध्यक्ष के पद पर काबिज होंगे। इसी दिशा में बढ़ते हुए राहुल गांधी और उनके करीबियों ने तैयारियां भी शुरू कीं।

## बदलता नजरिया

रोहित कौशिक।

प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल 'लैंसेट' में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2047 के बाद ही नीचे आ सकेगी। उस समय तक भारत की जनसंख्या करीब 1.61 अरब होगी, जिसे देश की आबादी का उच्चतम स्तर कहा जा रहा है। गौरतलब है कि 2010 से लेकर 2019 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर औसतन 1.2 फीसद रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस गति से 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर भारत संसार का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लैंसेट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के पहले प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में गिरती प्रजनन दर तथा बुजुर्गों की आबादी को तो ध्यान में रखा था लेकिन कुछ दूसरे महत्वपूर्ण रुझानों पर ध्यान नहीं दिया था।

सवाल यह है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिहाज से इस स्थिति को कैसे देखा जाए, जिसे इस सदी की शुरुआत से ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति माना जा रहा है और इसके बल पर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देने की उम्मीद बांधी जा रही है। शासन की ओर से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की सघन कोशिशें देश में इमर्जेंसी के दौरान ही हुई थीं। उसके राजनीतिक



परिणाम देखकर बाद की सरकारों ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, हालांकि जनसंख्या वृद्धि को वे भी एक समस्या ही मानती रहीं। 21वीं सदी आने के साथ धीरे-धीरे आबादी में युवाओं की बढ़ती संख्या के आधार पर इसे एक अच्छी चीज के रूप में देखने का चलन बढ़ा। मगर कोरोना के इस दौर ने नजरिये में फिर से बदलाव की जरूरत बताई है।

दरअसल कोरोना काल ने हमें यह बता दिया है कि अधिक जनसंख्या कई तरह से हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विषाणुजनित रोग फैलने का खतरा ज्यादा होता है। आज कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाने और लोगों

को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। जाहिर है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसे उपाय अपनाया मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह राहत की बात लगती है कि देश के नीतिदृष्टिनिर्माताओं ने तीनदशक पहले ही जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न खतरों को भांप लिया था। इसका फायदा यह हुआ कि इस दिशा में कुछ काम होते रहे। जबरन नसबंदी जैसे उपाय भले न दोहराए गए हों, लेकिन जनजागरण की मुहिम आधे-अधूरे ढंग से चलती रही।

आज भी सरकार करोड़ों रुपये इससे जुड़े विज्ञापनों और परिचर्चाओं पर खर्च कर रही है, हालांकि उसके ठोस फायदे नहीं दिख रहे। परिवार नियोजन नीतियों का भी ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आज के दौर में पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़ी समस्याओं की जड़ में भी लोगों की बेतहाशा बढ़ती संख्या ही है। दरअसल जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है, जिससे बाकी सभी समस्याओं के तार जुड़े हुए हैं।

जाहिर है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की आड़ लेकर हम जनसंख्या वृद्धि से आंखें नहीं मूंद सकते। हमें कुछ ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे जनता स्वयं इस मामले में रुचि ले।

सूटिक नवताल- 5440		* * * * *			
5	9	8	3	2	
	2	4			8
3	8	5	2	6	1
	7				9
9	3	6	8	7	4
	2	6			1
		5	2	7	1
6			4		7
		8	9	6	4
					2

सूटिक नवताल- 5439 का हल	
8	2
4	6
3	7
1	3
7	6
5	2
2	4
4	6
3	7
1	3
7	6
5	2
2	4
4	6
3	7
1	3

### अपना ब्लॉग शिक्षा का प्रसार कम

**मोहन।** हमें यह अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो सरकारी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से हासिल हो जाएगा। जब तक इस समस्या की गंभीरता आम जनता नहीं समझेगी, तब तक इस संबंध में किसी सार्थक परिणाम की उम्मीद रखना बेमानी है। आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस तबके में शिक्षा का प्रसार कम है। बड़ी संख्या में लोग निरक्षर भी हैं। ऐसी स्थिति में बड़े-बड़े विज्ञापन और परिचर्चाएं किस हद तक प्रभावी होंगी, यह भी विचारणीय है। इस तबके को गर्भनिरोध के साधन उपलब्ध कराना तथा इनका सही ढंग से इस्तेमाल सिखाना भी एक बड़ी चुनौती है। इमर्जेंसी के दौरान हुए प्रयोगों का अनुभव बताता है कि जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों और जन धारणों के बीच असंतुलन तथा संवादहीनता की स्थिति कायम रहेगी तो बेहतर परिणाम सामने नहीं आएंगे।

